षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि $\frac{\text{08 फाल्गुन, 1941 (श०)}}{\text{27 फरवरी, 2020 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	कृषि विभाग	..	..	..	01
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	01
(3)	राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग	..	..	..	01
				कुल योग --	03

आवासीय भूमि उपलब्ध कराना

5. <u>श्री भोला यादव</u>--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला सहित पूरे बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब उड़ाही के नाम पर तालाब के मुहार पर बसे दलित एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन लोगों के घर को उजाड़ने का काम किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा उक्त उजाड़े गये लोगों को बसाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत उजाड़े गये घर के लिये आवासीय जमीन उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

6. <u>श्री ललित कुमार यादव</u>--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''आधे किसानों को नहीं मिल सका डीजल अनुदान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के अनुदान प्रक्रिया बदलने के कारण राज्य से किसानों को खरीफ फसल में डीजल अनुदान की राशि सुखाड़ होने के बावजूद भी नहीं मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग की योजना के अनुसार किसानों को आवेदन करने के 25 दिनों के भीतर डीजल अनुदान की राशि उनके खातों में भेजने के प्रावधान के बावजूद खरीफ मौसम में 11.44 लाख किसानों के आवेदन में से मात्र साढ़े छह लाख किसानों को ही योजना का लाभ अबतक प्राप्त हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पदाधिकारियों की शिथिलता एवं लापरवाही की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

7. <u>श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी</u>--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 31 जनवरी, 2019 से राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगरपालिका में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दैनिक सफाई मजदूरों की सेवा समाप्त करने के कारण पूरे राज्य में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसका बुरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है एवं छटनीग्रस्त सफाई कर्मियों के परिवार के समक्ष भूखमरी की समस्या आ गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनता को गंदगी से निजात दिलाने एवं छटनीग्रस्त कर्मियों के रोजी-रोटी की व्यवस्था करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 फरवरी, 2020 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 151 (एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550